



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

जिमना, सनितार, १४ अगस्त, १९९३/२३ भाद्रपद, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय स्याकुलत, मण्डी; जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, ४ अगस्त, १९९३

संख्या: पी०सी० एम०-एम० एन० जी०-ए(६)/१९३/८९.—यतः ग्राम पंचायत बगैला, विकास खण्ड करसौग के लेखों की प्रेक्षक रिपोर्ट अवधि ४/८९ से ३/९२ के अन्तर्गत प्रकाश में आये निधि के अपहरण एवं दुरुपयोग के मामलों में श्री मोती राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बगैला को पंचायती राज नियमावली, १९७१ के नियम ७७ के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या ३४१६-३४२०, दिनांक ८ जून, १९९३ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि कब तक उन्हें नोटिस में वर्णित अनिवार्यताओं के लिये प्रधान पद ग्राम पंचायत बगैला से निवृत्त किया जाए।

२१२७-एनएन/९३-१४-८-९३—१,१५१.

(१४२९)

मूल्य: १.०० रुपया।

और क्योंकि श्री मोती राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बगैला से कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हो चुका है जिस पर विचार किया गया और उत्तर निम्नलिखित कारणों से असंतोषजनक है:—

1. उक्त श्री मोती राम, प्रधान ने आरोप संख्या 1 के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया है कि जो राशि मु 800/- (आठ सौ रुपये) दिनांक 29-7-89 को सहकारी बैंक से प्राप्त, की थी उसका हिसाब-किताब सचिव के पास था और रोकड़ इन्द्राज उस 'ारा किया जाना था परन्तु प्रधान का यह तर्क ठीक नहीं। प्रधान को यह चाहिए था कि यह तुरन्त सचिव से रोकड़ में इन्द्राज करवाता।

2. आरोप नम्बर 2 के सम्बन्ध में यह व्यान किया है कि दिनांक 25-5-89 से 25-7-90 जो अग्रिम धन का आरोप लगाया है वह अग्रिम धन के रूप में नहीं था बल्कि यह राशि लेकर अदायगी की थी। यह राशि मकद बाकी के रूप में सचिव के पास ही थी परन्तु प्रधान का यह कथन तर्क संगत नहीं। क्योंकि रोकड़ में किये गये इन्द्राजों के अनुसार यह राशि उनके नाम अग्रिम धन के रूप में दर्ज थी। उक्त राशि को बिना प्रयोग किये प्रधान ने 25-5-89 से 25-7-90 तक अनियमित रूप से अपने पास रखा।

3. आरोप नम्बर 3 के बारे में यह व्यक्त किया गया है कि चैक नं० 204348, दिनांक 1-5-92 के अधीन राशि सचिव द्वारा निकाली गई है और उसकी अदायगी भी सचिव द्वारा ही की गई है। परन्तु प्रधान का यह कथन ठीक नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमावली, 1975 के नियम 4 के अन्तर्गत केवल प्रधान और उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान ही सभा निधि का संचालन कर सकता है। इसलिये इस अनियमितता के लिये प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी है।

4. आरोप नम्बर 4 के सम्बन्ध में लगाया गया आरोप स्वीकार किया है।

5. आरोप नम्बर 5 के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया गया है कि मुबलिंग 300/- (तीन सौ) रुपये चौकीदार को अधिक भुगतान के लिए पंचायत सचिव ही स्पष्टीकरण दे सकता है। परन्तु प्रधान का यह कथन ठीक नहीं क्योंकि प्रधान संस्था के मुखिया होने के नाते तथा आहरण तथा वितरण की शक्तियां रखने के कारण यह देखना प्रधान का कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति विशेष को सभा निधि से अनियमित भुगतान नहीं।

6. आरोप संख्या 6 के बारे में प्रधान द्वारा व्यक्त किया है कि 80 बैग सिमेंट का ढुलवान करसोण से मतेहल तक तथा मतेहल से कुन्हों तक खच्चर द्वारा हुआ है। परन्तु अन्वेषण समय जो रसीदें प्रस्तुत की गईं उसके अनुसार 160 बैग का ढुलवान का व्यय डाला गया है। जिससे स्पष्ट है कि 80 बैग सिमेंट का ढुलवान दो बार दर्शाया गया है।

7. आरोप संख्या 7 के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया गया है कि 26 बैग सिमेंट जिसका मूल्य 3200/- (तीन हजार दो सौ) है वास्तव में ख्रय किया गया है और एफ०ओ०आर० मतेहल है। इसके बाद यह सिमेंट मजदूरों द्वारा ढुलवाया गया है क्योंकि अन्वेषण के समय श्रमिक जो ढुलवान पर लगाये गये थे, का कोई भी बाउचर प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए प्रधान का कथन तर्कसंगत नहीं है।

8. आरोप संख्या 8 के बारे में व्यक्त किया गया है कि बाउचर संख्या शून्य द्वारा श्री मुन्शी राम को वास्तविक रूप से अदायगी रेत सचिव द्वारा की गई है परन्तु प्रधान का यह कथन तर्कसंगत नहीं क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमावली, 1975 के नियम 4 के अन्तर्गत केवल प्रधान ही भुगतान कर सकता है सचिव नहीं।

9. आरोप संख्या 9 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि सभी सामान पंचायत कार्यालय में मौजूद है। परन्तु प्रधान का यह कथन असत्य है क्योंकि सचिव के ध्यान अनुसार कोई भी सामान कार्यालय में मौजूद नहीं था।

10. आरोप नम्बर 10 के सम्बन्ध में यह व्यक्ति किता है कि महिला मण्डल भवन का निर्माण मौका पर मौजूद है तथा यह कहना गलत है कि कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है परन्तु प्रधान ने इस आरोप के बारे में कोई भी उत्तर नहीं दिया है कि श्री मनी राम को क्यों स्वेच्छापूर्वक ठेका दिया ।

11. आरोप संख्या 11 के सम्बन्ध में यह व्यक्ति किता है कि विभिन्न कार्यों पर अनुदान राशि से अधिक व्यय सभा निधि से जनहित में किया गया है । प्रधान का यह व्यान तर्कसंगत नहीं क्योंकि यदि सभा निधि से कोई व्यय किया जाना होता तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमावली, 1975 के नियम 6(8) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ।

12. आरोप संख्या 12 के सम्बन्ध में व्यक्त किया है कि मस्ट्रोल नम्बर 4742 व 4743 का भुगतान आवश्यक हुआ है परन्तु अंशेक्षण के समय मस्ट्रोल सं० 4742 व 4743 एक ही माह के पाये गये तथा समान नाम लेखबद्ध किये गये हैं ।

13. आरोप संख्या 13 में यह लिखा है कि मजदूरों से अधिक अदायगी की वसूली कर ली है । अतः इस प्रकार आरोप सिद्ध हो जाता है ।

14. आरोप संख्या 14 के सम्बन्ध में प्रधान ने गलती मानी है । अतः आरोप सिद्ध हो जाता है ।

15. आरोप संख्या 15 के सम्बन्ध में व्यक्त किया गया है कि मेला मैदान कुफरीधार का निर्माण कार्य दो चरणों में हुआ है । एक चरण का मूल्यांकन 8847/- (आठ हजार आठ सौ सैतालीस) रुपये है तथा दूसरे चरण का मूल्यांकन करना शेष है । प्रधान का यह कथन ठीक नहीं क्योंकि रोकड़ में जो इन्द्राज किये गये हैं उनसे उपरोक्त कथन सत्य प्रतीत नहीं होता ।

और यह कि प्रधान के विरुद्ध सभा निधि के छलहरण/दुरुपयोग के गम्भीर आरोप हैं जिनकी जांच लाम्बित है । जांच के दौरान प्रधान द्वारा पंचायत अभिलेख में कोई फेरबदल न हो इसलिए उक्त प्रधान का प्रधान पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं समझा गया है ।

और क्योंकि अंशेक्षण के दौरान पता लगी अनियमितताएं इतनी गम्भीर हैं कि प्रधान द्वारा पद के निर्वाह में दुराचरण किया गया प्रतीत होता है और इस गम्भीर दुराचरण के लिए प्रधान को धारा 54(2)(बी) के अन्तर्गत पदच्युत किया जा सकता है ।

अतः मैं, संजीव गुप्ता, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1958 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री मोती राम प्रधान, ग्राम पंचायत बगैला, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी को तत्काल प्रधान पद से जनहित में निलम्बित करता हूँ तथा आदेश देता कि हूँ कि यदि उसके पास पंचायत की चल एवं अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी बगैला को सौंप दें तथा यह भी निर्देश देता हूँ कि वह निलम्बन कालावधि के दौरान उक्त निकाय की किसी कार्यवाही या कार्यवाहियों में भाग लेने से विवजित करता हूँ ।

संजीव गुप्ता,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (वि० प्र०) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।